

संपादकीय

आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हमने एक लंबा सफ़र तय किया है। चुनिंदा लोगों की पहुँच से निकल कर शिक्षा आज हर नागरिक तक पहुँच चुकी है। परंतु हमारे समाज में जेंडर, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म या अक्षमता से जनित असमानताएँ आज भी मौजूद हैं, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं। शैक्षिक पाठ्यचर्या में समय-समय पर बदलाव लाकर इन असमानताओं को संबोधित करने के प्रयास निरंतर जारी हैं ताकि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। पर क्या वास्तव में सभी को समान रूप से शिक्षा की सुविधाएँ मिल रही हैं? क्या हमारी कक्षाओं में सभी बच्चों को भागीदारी के समान अवसर मिल पाते हैं? क्या शैक्षिक प्रक्रिया में जेंडर भेद समाप्त हो चुका है? क्या हमारे विद्यालय व शिक्षक निःशक्त बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर देने में सक्षम हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर हम पूरे आत्म विश्वास से हाँ में दे सकने की स्थिति में शायद आज भी नहीं हैं। भारतीय आधुनिक शिक्षा के इस अंक में शामिल लेखों के माध्यम से इनमें से कुछ प्रश्नों पर चर्चा की गई है।

साधना 'सक्सेना' का लेख 'शिक्षा में समानता के सरोकार' के संदर्भ में बालिकाओं के लिए विशेष आवासीय विद्यालय-योजना की पड़ताल करता है। इस लेख को पुनः प्रकाशित किया जा

रहा है। अरूण कुमार 'वर्मा' ने भारतीय संदर्भ में 'समावेशी शिक्षा' की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए अपने लेख में, विद्यालयों में सभी बच्चों के समावेशन के लिए शिक्षक की तैयारी पर विशेष जोर दिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पश्चात् शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में अनेक कार्यक्रम चलाये गये। बिहार भी ऐसे राज्यों में शामिल है। आदित्य 'सिन्हा' और पारस 'रत्न' ने अपने लेख के माध्यम से बिहार राज्य में 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला है।

विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विद्यालय का वातावरण स्वच्छ होना जरूरी है, साथ ही प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास किया जाना चाहिए। जे.डी. 'सिंह' ने अपने शोधपरक लेख में इसी संदर्भ में राजस्थान के प्राथमिक विद्यालयों में चलाये जा रहे 'शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम' का विवरण प्रस्तुत किया है।

कंप्यूटर, इंटरनेट व अन्य संचार माध्यमों के बावजूद पुस्तकें आज भी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहीं-कहीं तो आज भी विद्यार्थियों के पास केवल पाठ्य पुस्तकें ही ऐसा साधन होती हैं, जिनके माध्यम से वे ज्ञान प्राप्त करते हैं। शालिनी 'नागर' ने विद्यार्थियों की दृष्टि

से एन.सी.ई.आर.टी द्वारा प्रकाशित उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किया है। इस अंक में वेंडी 'डोनीज़र' की विवादित पुस्तक 'हिन्दूज़- एन आल्टरनेटिव हिस्ट्री' (2009) की आलोचनात्मक टिप्पणी शामिल है, जिसे शंकर 'शरण' ने लिखा है।

अनुभव बताते हैं कि माताओं की शिक्षा बच्चों की शिक्षा और विकास को प्रभावित करती है। पढ़ी-लिखी माताएँ बालिकाओं को शिक्षित करने संबंधी निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। रमेश धर 'द्विवेदी' के शोधपरक लेख से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि शिक्षित माताएँ अपनी बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, अतः यदि हम शिक्षित माताएँ चाहते हैं, तो आज बालिकाओं को शिक्षित करना बेहद ज़रूरी है।

यद्यपि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है परंतु अच्छे हिंदी शिक्षकों का अभाव है, इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जिम्मेदार हैं। तारकेश्वर 'गुप्ता' का शोध-आधारित लेख 'बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों को हिंदी अभ्यास शिक्षण' के दौरान आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करते हुए उनके समाधान भी सुझाता है।

अभी हाल ही में हमने शिक्षक दिवस मनाया और प्रतिभाशाली शिक्षकों को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार भी दिये गये। आपके आस-पास भी ऐसे शिक्षक होंगे जो प्रतिभाशाली हैं और जिन्होंने अपने स्तर पर नवाचार भी किये हैं परंतु कहीं उन नवाचारों को बाँटा नहीं है। ऐसे नवाचार हम सभी के लिए लाभदायक हो सकते हैं। ऐसे नवाचारी शिक्षकों के कार्यों संबंधी लेखों का हम हृदय से स्वागत करेंगे।

अकादमिक संपादकीय समिति